यूपीडा को एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बसाने के लिए धन देगा बीडा

लखनऊ। प्रदेश के पांचों एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारों को तेजी से विकसित करने का रास्ता खुल गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) को जरूरी बजट का संशय दूर हो गया है। अब औद्योगिक गलियारों को विकसित करने पर होने वाले खर्च की धनराशि नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) देगा। इन्हें विकसित करने पर जो खर्च आएगा, उसे बीडा के लिए आवंटित 3000 करोड़ रुपये में से यूपीडा को लोन के रूप में दिया जाएगा।

फैसला 03

यूपीडा के पास नहीं है खुद का वित्तीय स्रोत

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह के मुताबिक इस निर्णय से राज्य सरकार पर आने वाला खर्च लोन के रूप में होगा। केंद्र से इस परियोजना में कोई मदद नहीं ली जाएगी। इसी के साथ औद्योगिक गलियारों को तय समयसीमा में पूरा किया जा सकेगा। वहीं, औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज होगी और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। ब्यूरो

गंगा एक्सप्रेसवे के जीएसटी का 2782 करोड़ रुपये देगा यूपीडा

लखनऊ। गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने दो प्रस्तावों को मंजूर किया है। पीपीपी मोड के कार्यों पर जीएसटी 12 से 18 फीसदी होने से अतिरिक्त छह फीसदी जीएसटी की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) करेगी। इस प्रस्ताव से यूपीडा पर 2781.97 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में कैश फ्लो का संकट दूर करने के लिए भुगतान की शर्त में राहत दी गई है। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि कैबिनेट में कनेक्टिविटी को लेकर लिए ये फैसले औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे वैश्विक निवेश सम्मेलन में किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने में तेजी आएगी और नए निवेश का रास्ता खुलेगा। ब्यूरो

फैसला 04

ललितपुर में पशुपालन विभाग की जमीन पर बनेगा फार्मा पार्क

लखनऊ। गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने दो प्रस्तावों को मंजूर किया है। पीपीपी मोड के कार्यों पर जीएसटी 12 से 18 फीसदी होने से अतिरिक्त छह फीसदी जीएसटी की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) करेगी। इस प्रस्ताव से यूपीडा पर 2781.97 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में कैश फ्लो का संकट दूर करने के लिए भुगतान की शर्त में राहत दी गई है।

फैसला 05

औद्योगिक विकास विभाग को हस्तांतरित होगी जमीन

यूपीसीडा करेगा विकास, एक लाख करोड़ का निवेश

औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि कैबिनेट में कनेक्टिविटी को लेकर लिए ये फैसले औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे वैश्विक निवेश सम्मेलन में किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने में तेजी आएगी और नए निवेश का रास्ता खुलेगा। ब्यूरो